खंड 1, मई 2020

‘साधारण’ लोगों के असाधारण कार्य

महामारी एवं लॉकडाउन से परे

समुदायों, नागरिक समाज संगठनों एवं
सरकारी एजेंसियों के लिए उदाहरण,
पाठ एवं विशिष्ट सिफारिशें

अनुक्रमणिका

परिचय 01

खाद्य 03

बाज़ार 08

आजीविका 15

स्वास्थ्य 28

योगदानकर्ताओं, उद्धरण तथा विकल्प संगम
के लिए अंतिम पृष्ठ देखें

परिचय : इस दस्तावेज की जरुरत क्यों?

मार्च 2020 के बाद से लेकर अबतक, कोविड – 19 से जुड़े संकटों ने भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है। देश के 90% से अधिक कामगार अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्रों से जुड़े हैं और प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के बहुसंख्यक उत्पादक अपनी आजीविका के लिए रोजमर्रा के विपणन पर निर्भर हैं। उत्पादन इकाइयों के बंद होने और बाज़ार तक पहुंचने की असमर्थता का मतलब उनकी आजीविका का तत्काल नुकसान है। प्रवासी श्रमिकों के लिए, घर से दूर रहने का अतिरिक्त प्रभाव होता है, और सार्वजनिक परिवहन के अचानक बंद होने से वे सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं। भोजन, पानी, आवास एवं अन्य बुनियादी जरूरतों के अभाव ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है खाद्य।

अब जबकि तात्कालिक मानवीय संकट साफ़ दिखायी दे रहा है और इसने नागरिक समाज एवं विभिन्न राज्य सरकारों की ओर से राहत प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से स्वतः स्फूर्त पहलों को प्रेरित किया है, यंत्रणा के मूल कारणों को दूर करने के प्रयास आम तौर पर बेहद ही कम हैं। कोविड संकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था, समाज एवं राजनीति की गहरी खामियों को तीखे ढंग से उजागर किया है। इन खामियों में उत्पादकों एवं कामगारों और उनमें से भी महिलाओं, दलितों, आदिवासियों एवं अन्य वैसे लोगों, जोकि पहले से ही हाशिए पर हैं, की चरम लाचारगी शामिल है। इनमें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के आदान – प्रदान एवं व्यापार पर निर्भर रहने की मूढ़ता भी शामिल है। इसने पारिस्थितिक तबाही और सामाजिक-आर्थिक अभाव के बीच को गहरे संबंधों को दिखाया है। कुल मिलाकर, 'विकास' के प्रमुख नमूनों (मॉडलों) की असमानता और अस्थिरता को स्पष्ट रूप से सामने लाया है।

ऐसी परिस्थिति में यह जरुरी है कि न सिर्फ तात्कालिक राहत एवं पुनर्वास के उपायों की व्यवस्था हो, बल्कि इसके साथ – साथ आर्थिक, सामजिक एवं राजनीतिक रवैये के बारे में भी बुनियादी रूप से पुनर्विचार किया जाये। भारत को, दुनिया के बाकी हिस्सों की तरह, पूरी तत्परता से कल्याण के उन वैकल्पिक रास्तों को खोजने की जरूरत है, जो सभी के लिए सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित करने और हमें पारिस्थितिक स्थिरता की ओर बढ़ने में मदद करे। इसे (ग्रामीण, कस्बाई, शहरी) समुदायों के आत्म-सशक्तीकरण, भोजन, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा, आश्रय, शिक्षा एवं अन्य बुनियादी जरूरतों तथा आकांक्षाओं को प्रशासित

परिचय : इस दस्तावेज की जरुरत क्यों?

एवं प्रबंधित करने की क्षमता के निर्माण को इस तरीके से प्रेरित करने की जरुरत है, जो भरसक आत्मनिर्भरता एवं स्वावलंबन की ओर ले जाये।

एक ऐसे समाज की खातिर एक आंदोलन - अपने वास्तविक अर्थों में स्वराज - केवल सैद्धांतिक नहीं है। ऐसा पहले से ही देश भर में सैकड़ों पहलों के जरिए हो रहा है। दस्तावेजों की इस श्रृंखला में हम ऐसे उदाहरण पेश करना चाहते हैं, जिससे महत्वपूर्ण सबक सीखे जा सकें और इन सबकों को देश के अन्य हिस्सों में इसी तरह के परिणाम हासिल करने के लिए ढाला जा सके। हम यह दिखाना चाहते हैं कि कोविड - 19 के दौरान साबका पड़ने वाले हरेक प्रमुख समस्या (जो निश्चित रूप से काफी लंबे समय से हमारे इर्दगिर्द मौजूद हैं, लेकिन अब काफी तीव्रता के साथ दिखाई दे रहे हैं) का समाधान है और विभिन्न समुदायों, नागरिक समाज या सरकारी एजेंसियों द्वारा पहले ही देश के किसी न किसी हिस्से में इसे साबित भी किया गया है।

हम आपको इन सबकों को समझने और उनसे सीखने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप इस दस्तावेज़ को अपनी मनपसन्द मीडिया और भाषा में वितरित कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसे उदाहरण हैं, जिनके बारे में आपको लगता है कि दूसरों को जानना चाहिए, तो कृपया हमें बताएं!

संपर्क:

सामान्य समन्वय: जुही पाण्डेय, studiojuhi@gmail.com, 9820039110

इन पहलों से प्राप्त महत्वपूर्ण सबकों को अन्य साइटों और समुदायों (प्रत्येक कहानी में प्रदान किए गए विशिष्ट संपर्कों के अलावा) को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए:
गिज्स स्पूर: gijs@auroville.org.in, 9943820241 (सिर्फ व्हाट्स ऐप/ एसएमएस)

समस्या : गांवों में खाद्य असुरक्षा

समाधान: समुदायों द्वारा खाद्य संप्रभुता एवं सुरक्षा

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

(बाएं) नरसम्मा और पीआरए, पास्तापुर में अन्य डीडीएस महिलाएं; (दाहिने) संघम ऑर्गेनिक्स शॉप, ज़हीराबाद

डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, तेलंगाना के दलित एवं आदिवासी महिला किसान

पिछले 25-30 वर्षों में, तेलंगाना के ज़हीराबाद जिले की कई हजार दलित और आदिवासी (देहाती) महिलाओं ने एक कृषि क्रांति की शुरुआत की है। कुल 70 से अधिक गांवों में महिला समूहों एवं डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी की सदस्यता के माध्यम से, उन्होंने अपने शुष्क क्षेत्रों में पारंपरिक बीज और पशुधन विविधता (विशेष रूप से बाजरा) को पुनर्जीवित किया है। वे पूरी तरह से जैविक और स्थानीय वस्तुओं की ओर मुड़ी हैं। उन्होंने मिश्रित और बहुफसली खेती को पुनर्जीवित किया है। प्रत्येक गांव में आसान पहुंच के लिए अनाज बैंक बनाये हैं। और महिलाओं के भूमि अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी हैं। इस प्रक्रिया में, उन्होंने खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण की स्थितियों को पर्याप्तता एवं पोषणयुक्त स्वास्थ्य में बदल दिया। वे गरीबों को सस्ता, पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली और हैदराबाद में 100 परिवारों के साथ कॉन्फर्म नाम की एक निर्माता-उपभोक्ता व्यवस्था चलाती हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस पहल ने उन्हें सम्मान दिलाया, जोकि एक जातिवादी एवं लैंगिक असमानता वाले समाज में कभी नहीं मिला था और संयुक्त राष्ट्र के भूमध्यरेखा पुरस्कार (इक्वेटर अवार्ड) का हकदार बनाया।

समस्या : गांवों में खाद्य असुरक्षा

समाधान: समुदायों द्वारा खाद्य संप्रभुता एवं सुरक्षा

कोविड -19 की वजह से हुए लॉकडाउन के दौरान, इन महिलाओं के परिवारों के पास न केवल खुद के लिए, बल्कि भूमिहीन परिवारों के साथ साझा करने, जिला राहत उपायों के लिए दान करने तथा जहीराबाद कस्बे में नगरपालिका / पुलिस / स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को हर दिन 1000 गिलास बाजरे का दलिया उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है।

सबक

न्यूनतम बाहरी वस्तुओं के साथ, स्थानीय कृषि-पारिस्थितिक स्थितियों का सम्मान करते हुए, स्थानीय ज्ञान पर निर्भर रहते हुए और स्थानीय बाजारों को सुविधाजनक बनाते हुए, सूखे क्षेत्रों में भी समुदाय द्वारा खाद्य संप्रभुता और सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। भारत का कृषि विकास मॉडल पूरी तरह से इसके उलट है और इसमें आमूल परिवर्तन की जरुरत है।

संपर्क

जयश्री चेरुकुरी, jayasri.dds@gmail.com

डीडीएस के साथ कोविड – काल बातचीत भी देखें:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-self-reliant-village.html

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

फोटो सौजन्य डीडीएस

(बाएं) शामलाम्मा (डीडीएस), इप्पापल्ली गांव, तेलंगाना; (दाहिने) कोविद -19 संकट के दौरान रागी दलिया का डीडीएस वितरण

समस्या : गांवों में खाद्य असुरक्षा

समाधान: समुदायों द्वारा खाद्य संप्रभुता एवं सुरक्षा

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

(बाएं) जैविक फसलों के साथ केडिया किसान; (दाहिने) अमृतपानी संकेत के साथ केडिया जैविक क्षेत्र

केडिया जैविक गांव, बिहार

बिहार के जमुई का केडिया गांव, जिसमें 97 किसान परिवार शामिल हैं, ने 2014 में पारिस्थितिक कृषि के लिविंग स्वाइल दृष्टिकोण को अपनाया। इसका उद्देश्य बायोमास का उपयोग करके मिट्टी का कायाकल्प करना था और खेती में रसायनों के उपयोग को बंद कर जैव विविधता को बहाल करना था। उससे पहले, यह गांव कृषि - रसायन बीज कंपनी - व्यापक सिंचाई- चावल और गेहूं की एकफसली खेती के चक्र में फंस गया था, जिसने पूरे भारत में 'हरित क्रांति' के किसानों को प्रभावित किया है।

ग्राम समुदाय ने, ग्रीनपीस इंडिया एवं राज्य कृषि विभाग के सहयोग से, तथा कुछ खेतों में शुरूआती परीक्षण के बाद, 4-5 वर्षों में अपनी खेती के पूरे तौर -तरीकों को बदल दिया। अब वे गांव के बाहर से किसी भी वस्तु का उपयोग किए बिना, जैविक तरीके से अपनी जरुरत के सभी खाद्य पदार्थों (नमक और चीनी को छोड़कर) को उगाते हैं। संवर्धित जैव विविधता कीटों से सुरक्षा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद करती है। इसने खुले कुओं का कायाकल्प कर दिया है, जो अब घरेलू और सिंचाई के लिए साल भर के लिए पर्याप्त हैं और बोरवेल के उपयोग को बंद कर दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह परिवर्तन किसानों एवं सरकारी अधिकारियों, दोनों, की मानसिकता में बदलाव के कारण आया है।

इस पहल ने बिहार सरकार को पारिस्थितिक खेती के लिए अधिक अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रभावित किया है। इसका तीसरा कृषि रोडमैप प्रत्येक जिले में एक जैविक कृषि मॉडल गांव विकसित करने, सभी राजमार्गों के साथ-साथ गंगा नदी के दोनों किनारों पर जैविक गलियारे बनाने तथा 2020 तक 21000 एकड़ भूमि को जैविक भूमि में परिवर्तित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

समस्या : गांवों में खाद्य असुरक्षा

समाधान: समुदायों द्वारा खाद्य संप्रभुता एवं सुरक्षा

कोविड -19 महामारी के दौरान, ग्राम समुदाय ने पूरी सक्रियता से सुरक्षात्मक मास्क बनाया तथा वितरित किया है और आवश्यक व्यवहारगत परिवर्तनों को अपनाया है। लॉकडाउन की वजह से दैनिक वेतनभोगियों एवं कुछ किसानों की आजीविका पर मडराते खतरे को भांपते हुए केडिया के किसानों ने सामुदायिक एकजुटता की मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम ने आसपास के गावों के उन 426 परिवारों को सूखा राशन किट (जैविक चावल, गेहूं का आटा, दाल, सरसों का तेल एवं चना) वितरित किया है, जो सरकारी राशन वितरण कार्यक्रमों के पात्र नहीं हैं। ग्राम समुदाय इन परिवारों की पहचान करने और उनतक पहुंचने के लिए स्थानीय मीडिया, पंचायत सदस्यों और नागरिक समाज समूहों के साथ जुड़ा हुआ है।

सबक

बाहरी एजेंसियों पर न्यूनतम निर्भरता के साथ जैविक, विविध, स्थानीय रूप से प्रबंधित खेती खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में मदद कर सकती है, जो ग्राम समुदायों को कोविड -19 जैसे संकटों से निपटने में सक्षम बना सकती है। इसके अतिरिक्त, वे उनलोगों की मदद करने की स्थिति में भी होंगे जो उनकी जैसी स्थिति में नहीं हैं। जबतक यह बदलाव इस प्रक्रिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थानीय क्षमता विकसित करने की दिशा में उन्मुख है, सरकारी एजेंसियों एवं नागरिक समाज से प्राप्त नीतिगत तथा कार्यक्रम आधारित समर्थन इसमें उल्लेखनीय रूप से मददगार साबित हो सकता है।

संपर्क

इश्तियाक अहमद, ishteyaque.ahmed@greenpeace.org, 7632988788

फोटो सौजन्य केडिया के किसान

केडिया COVID राहत कार्य

गांवों में खाद्य असुरक्षा के लिए सिफारिशें

- छोटे उत्पादकों (जो भारत में उत्पादकों का अधिकांश हिस्सा हैं), जिनमें किसान, पशुपालक, मछुआरे, वनवासी, शिल्पकार शामिल हैं, को प्राथमिकता दें।
- गांव एवं ग्राम समुदाय स्तर पर ऐसे लोगों, विशेष रूप से बेहद कमजोर वर्गों, के संगठित होने को प्रेरित करें। यह सुनिश्चित करें कि भूमि और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों तक उनकी पर्याप्त पहुंच हों।
- उच्चतम प्राथमिकता के तौर पर भोजन के साथ जैविक, जैव विविधता, स्थानीय रूप से पर्यावरण के प्रति संवेदनशील खेती का समर्थन, प्रोत्साहन एवं उसपर अमल करें। सामुदायिक अनाज बैंकों की स्थापना, फसलों एवं पशुधन के भंडारण की पारंपरिक प्रणालियों का निर्माण तथा स्थानीय आनुवंशिक सामग्री के हस्तांतरण को प्रोत्साहित करें।
- शुष्क भूमि एवं वर्षा आधारित खेती को उच्च प्राथमिकता देते हुए पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। बोरवेल और पानी की गहन जरुरत वाले फसलों के उपयोग को प्रोत्साहित करें। पानी के अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने वाले खुले कुओं और अन्य पारंपरिक एवं नई प्रणालियों को पुनर्जीवित करने को प्रोत्साहित करें।
- छोटे उत्पादकों को इस तरह की खेती की ओर मुड़ने में सक्षम बनाने, संक्रमण काल में मदद के लिहाज से रासायनिक उर्वरक एवं जैविक वस्तुओं के लिए हरित क्रांति से संबंधित किसी भी अन्य अनुदान तथा सुविधाओं को हस्तांतरित करें। लेकिन इस तरह की मदद को आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होना चाहिए, न कि उसे अनवरत रूप से सरकार पर निर्भरता का वायस बन जाना चाहिए।
- बड़े उत्पादकों, विशेष रूप से कॉरपोरेट घरानों, को कराधान एवं अन्य माध्यमों के जरिए सक्रिय रूप से हतोत्साहित करें।
- सार्वजानिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन, आंगनबाड़ी एवं अन्य ऐसे कार्यक्रमों (स्थानीय समुदायों को उन्हें चलाने के लिए सशक्त बनाते हुए), अस्पतालों, स्कूलों एवं कॉलेजों जैसे सार्वजानिक संस्थानों तथा निजी संस्थानों के लिए स्थानीय उपज की खरीद को प्राथमिकता दें। स्थानीय कृषि संबंधी परिस्थितियों एवं छोटे उत्पादक प्रणालियों के अनुकूल फसलों, पशुधन, मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करें।
- और अधिक व्यापार विनियमन / मुक्त व्यापार संधियों पर हस्ताक्षर करके खाद्य संप्रभुता एवं सुरक्षा को और आगे खतरे में न डालें। ऐसे किसी भी मौजूदा समझौते से बाहर निकलें।

समस्या: शहरों में किसानों का बाज़ार तक पहुंच का अभाव तथा अपर्याप्त या स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता

समाधान: किसान – उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क

उदहारण 01 | उदहारण 02 | उदहारण 03 | सिफारिशें

फोटो सौजन्य मानस अरविन्द

गुड़गांव किसान बाज़ार (गुड़गांव फार्मर्स मार्केट)

गुड़गांव जैविक किसान बाज़ार (गुड़गांव आर्गेनिक फार्मर्स मार्केट, [जीओएफएम]) एक साप्ताहिक बाज़ार है, जो 2014 से लेकर कोविड लॉकडाउन तक लगातार चला है। इस पहल ने गुड़गांव के आसपास के लगभग 20 जैविक किसानों को गुड़गांव में रहने वाले 500 से अधिक परिवारों के साथ जोड़ा है। लॉकडाउन होने के साथ, यह बाजार ऑनलाइन हो गया, जहां से ग्राहकों के सामान का थैला उनके घर तक पहुंचाया गया। अबतक, यह एक लाभ-मुक्त और पूरी तरह से स्वैच्छिक प्रयास पर आधारित बना हुआ है और नैतिकता के एक सनद के साथ चलता है। ज्यादातर किसान, छोटे से बड़े तक, स्थानीय हैं। वे जीओएफएम के मूल्यों का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। इस बाज़ार में स्टॉल स्थापित करने वाले किसान और एग्रीगेटर (जैविक स्टोर) दोनों हैं। कीमतें स्वयं किसानों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

स्वयंसेवक एवं कुछ उत्साही ग्राहक इस बात का 'सत्यापन' करने के लिए नियमित रूप से खेतों का दौरा करते हैं कि वे वाकई जैविक हैं। जीओएफएम न तो इस किस्म के कदम में विश्वास करता है और न ही जैविक प्रमाणन को प्रोत्साहित करता है। वह भरोसे के रिश्ते के साथ काम करता है। ऐसे मामले सामने आये हैं जब किसानों ने धोखाधड़ी की और उन्हें निकल जाने को कह दिया गया। लेकिन जैविक बने रहने का प्रोत्साहन इतना अधिक है कि ऐसे मामले अत्यंत दुर्लभ होते हैं।

मानस अरविन्द, पहले से किसान बाज़ार चला रहे या ऐसा ही एक बाज़ार चलाने के इच्छुक लोगों के ऑनलाइन समूह farmers-markets-india@googlegroups.com, के संस्थापकों में से एक एवं सह – प्रबंधक हैं ।

समस्या: शहरों में किसानों का बाज़ार तक पहुंच का अभाव तथा अपर्याप्त या स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता

समाधान: किसान – उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क

उदहारण 01 | उदहारण 02 | उदहारण 03 | सिफारिशें

सबक

प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को पड़ोस के गांवों, कस्बों एवं शहरों के साथ किसानों, पशुपालकों, मछुआरों, वनवासियों एवं शिल्पकारों को बाज़ार स्थापित करने के लिए प्रेरित करते हुए जोड़ा जा सकता है, जहां वे सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं या जहां उत्तम तौर – तरीकों वाले छोटे स्तर के व्यापारी / एग्रीगेटर अपना स्टाल लगा सकते हैं। अत्यंत आवश्यक सामग्रियों को एक तैयार स्थानीय बाज़ार मिलेगा। इससे लंबी – दूरी के व्यापार, जोकि नाजुक मामला होता है (जैसाकि कोविड ने दर्शाया है!) और जहां मुनाफ़ा ज्यादातर बिचौलियों एवं कंपनियों द्वारा कमाया जाता है, की जरुरत व्यापक रूप से कम होगी।

हालांकि, ऐसी व्यवस्था में जैविक खाद्य पदार्थों को खरीद सकने का सामर्थ्य एक अहम चुनौती होगी। कम आय वाले उपभोक्ता के लिए भी इसे कैसे सुलभ बनाया जा सकता है? प्रति – सहायिकाएं (क्रॉस – सब्सिडी), नागरिक समाज तथा राज्य द्वारा नीतिगत / कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप इसमें कुछ हद तक मददगार साबित हो सकते हैं।

संपर्क

मानस अरविन्द, manasarvind@gmail.com

कोविड – काल बातचीत भी देखें:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-1-farmers-markets.html

फोटो सौजन्य मानस अरविन्द

फोटो सौजन्य दयानंद निकम

सतारा के किसान चुनिंदा स्थानों पर अपनी उपज का परिवहन करते हुए

कोविड – 19 के दौरान सतारा 'डायरेक्ट टू होम' आदान - प्रदान

रबी की कटाई के मौसम के ठीक बाद कोरोना महामारी के फैलने के साथ सतारा के किसानों को दो चुनौतियों का सामना करना पड़ा – फसल को काटने एवं उठाने के लिए प्रवासी मजदूरों एवं उनकी उपजों के परिवहन के लिए ट्रक चालकों की अनुपलब्धता। इस स्थिति की वजह से बिचौलियों ने या तो उनकी उपजों को नहीं खरीदा या फिर बेहद ही कम दामों पर खरीदा। मजदूरों के अचानक उलट पलायन ने राज्यभर में कृषि क्षेत्र को अस्त - व्यस्त कर दिया और केंद्र की ओर से अपर्याप्त सहायता मिली।

सतारा स्थानीय प्रशासन ने किसानों, स्थानीय मंडी के बिचौलियों, नागरिक समाज एवं सामाजिक नवप्रवर्तनकर्ताओं के साथ मिलकर इस समस्या के स्थानीय समाधानों की तलाश शुरू की। एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश पोल के साथ मिलकर नगरपालिका स्तर पर उप मुख्य अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख संचित धूमल ने इस किस्म की पहल के लिए आवश्यक संरचनात्मक जरूरतों का पता लगाया। किराना, दूध, सब्जियां और फल जैसी आवश्यक चीजों को सीधे घर तक आपूर्ति करने का उनका प्रयोग सफल रहा। इस प्रयोग से किसानों को मदद मिली और शारीरिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हुआ। सतारा नगरपालिका के सहयोग से इलाके के लगभग 38 किसान अपने खराब होने वाले उत्पादों को एकत्र कर रहे हैं, उन्हें चुनिंदा स्थानों पर ले जा रहे हैं और ताजा उपज की तलाश में

भटक रहे परिवारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग कर रहे हैं। वे पहले की तुलना में, जब उन्हें स्थानीय मंडी (बाजार) में बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था, अधिक पैसा कमा रहे हैं।

किसानों को अपने उपज का परिवहन करने के लिए मोटरवाहनों का एक बेड़ा चलाने की अनुमति मिली। यह कदम किसानों के एक समूह के लिए सामानों के सीधे घर तक आपूर्ति का एक मॉडल विकसित करने का एक अवसर बन गया। ये मोटरवाहन, जो 1200-1500 रुपये रोजाना की दर से किराए पर लिए जाते हैं, विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में जाते हैं और उत्पादों को सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। अप्रैल 2020 तक, वे लगभग 250 घरों तक पहुंचे।

यह मॉडल भीड़भाड़ वाली मंडियों की तुलना में अधिक सुरक्षित विकल्प है, जहां शारीरिक दूरी को लागू करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। किसानों के लिहाज से, बिचौलियों को खत्म करने से उनके मुनाफे में काफी वृद्धि हुई है। ताजी उपज की आसानी से उपलब्धता एवं उचित कीमतों के कारण ग्राहकों को यह बेहतर लगता है। उपज की नियमित उपलब्धता उन्हें अनावश्यक रूप से जमाखोरी करने से रोकती है।

सबक

किसानों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष, स्थानीय, और विकेंद्रीकृत जुड़ाव की सुविधा उत्पादकों, उपभोक्ताओं और सामान्य रूप से पर्यावरण के लिए लाभकारी हो सकती है। यह स्थानीय सामुदायिक सशक्तीकरण को जन्म दे सकता है। गांव एवं शहरों के बीच सकारात्मक संबंध बना सकता है और सामान्य तौर पर कोविड जैसे संकटों से निपटने के लिए समुदायों की क्षमता को बढ़ाता है।

अब चुनौती यह देखना है कि क्या यह मॉडल कोविड –19 संकट की अवधि के बाद भी जारी रह सकता है; और यह भी कि क्या अधिक जैविक, स्वस्थ कृषि पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

संपर्क

संचित धूमल - उप मुख्य अधिकारी एवं प्रमुख, स्वास्थ्य विभाग, सतारा नगरपालिका (सतारा कलक्टर : 02162232175)

फोटो सौजन्य नवदर्शनम्

(बाएं) नवदर्शनम् स्वयं सहायता समूह गतिविधियाँ; (दाहिने) नवदर्शनम् खाद्य सहकारिता के सदस्य

नवदर्शनम् समुदाय द्वारा समर्थित कृषि

वर्ष 1990 में स्थापित नवदर्शनम् (http://navadarshanam.org/) एक छोटा सा समुदाय है, जो बेंगलुरु से लगभग 50 किमी दूर एक आरक्षित वन से सटे तमिलनाडु के ग्रामीण इलाके में स्थित है। यह समुदाय पारिस्थितिक संतुलन एवं आतंरिक शांति की चाहत में आधुनिक जीवनशैली एवं सोच के विकल्प की तलाश में संलग्न है। इसके निवासियों ने पर्यावरण-बहाली एवं जंगल संरक्षण, वैकल्पिक ऊर्जा, स्थायी जैविक खेती, जल संचयन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र के साथ-साथ पौष्टिक एवं पारंपरिक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में भी विभिन्न प्रयोग किये हैं।

इस समुदाय ने स्थानीय ग्रामीणों द्वारा संचालित एक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रूप में खाद्य पदार्थों से जुड़ी एक पहल, जो ग्रामीण आजीविका एवं पारंपरिक कौशल और कृषि पारिस्थितिकी प्रणालियों का संरक्षण करते हुए, बेंगलुरु तथा अन्य जगहों पर शहरी उपभोक्ताओं को जैविक एवं संपूर्ण भोजन का विकल्प प्रदान करती है, की शुरुआत करने एवं उसका मार्गदर्शन करने में भी सहायता दी है। वर्ष 2017 में, इस स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ने एक समुदाय समर्थित खेती (सीएसए) की पहल शुरू की, जो सब्जियों, फलों और किराने का सामान (पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के साथ) के साप्ताहिक थैले के लिए शहरी ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं के आधार पर स्थानीय जैविक किसानों को अपनी गतिविधियों के संचालन की योजना बनाने में मदद करती है। इस उद्यम से प्राप्त सभी

व्यावसायिक लाभ खाद्य पदार्थों के ग्रामीण उत्पादकों को दिये जाते हैं। समान एकड़ की खेती के दौरान सीएसए ने मार्गदर्शन का पालन करने वाले किसानों की आय में 10 से लेकर 20 गुणा तक लगातार वृद्धि की है।

तमिलनाडु की सीमा के ठीक भीतर होने के कारण, कोविड – संबंधी लॉकडाउन की पृष्ठभूमि में सीमा – पार आपूर्ति के लिए दो राज्यों से परमिट हासिल करना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन सीएसए की आपूर्ति अबतक बिना किसी रुकावट के जारी है। अन्यथा स्थानीय किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता। इसके अलावा, बंगलुरु के रेड जोन में बाज़ार तक सीमित पहुंच होने के कारण शहरी उपभोक्ता इस बात के लिए बेहद आभारी हैं कि सीएसए ताज़ा स्थानीय जैविक उत्पादों की आपूर्ति जारी रखने में कामयाब रहा है। वितरण के लिए बने ड्रॉप स्थान और सभी खुले क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया गया है कि सदस्य शारीरिक दूरी के मानदंडों का पालन करने तथा संक्रमण के जोखिम को कम करने में सक्षम होंगे।

सबक

ऊपर वर्णित अन्य दो पहलों से सीखे गये सबकों के अलावा, नवदर्शनम् का उदाहरण भी कोविड से संबंधित लॉकडाउन की गंभीर सीमाओं से उबरते हुए ग्रामीण एवं शहरी इलाकों के बीच एक बेहतर जुड़ाव के लचीलेपन की ओर इशारा करता है।

संपर्क

गोपी शंकरासुब्रमणि, navadarshanam@gmail.com

फोटो सौजन्य नवदर्शनम्

नवदर्शनम् खाद्य सहकारिता के सदस्य

शहरों में किसानों का बाज़ार तक पहुंच का अभाव तथा अपर्याप्त या स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता के बारे में सिफारिशें

- प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं, दोनों, तक आसानी से पहुंच संभव बनाते हुए स्थानीय उत्पादक बाजारों को विकेन्द्रीकृत तरीके से स्थापित करने की सुविधा प्रदान करें। ऐसा दो ग्रामीण क्षेत्रों (उपयुक्त वस्तु - विनिमय समेत) या गांवों और कस्बों / शहरों के बीच किया जा सकता है।
- इन बाजारों में जैविक, छोटी–जोत वाले किसानों या कारीगरों पर आधारित उत्पादों को प्रोत्साहित करें। यदि बड़े उत्पादकों को भी अनुमति दी जाती है, तो यह सुनिश्चित करें कि वे हावी न हों।
- ऐसे बाज़ारों में कॉर्पोरेट कंपनियों को प्रवेश करने की अनुमति न दें।
- उत्पादकों और उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी उपलब्ध कराकर उचित मूल्य-निर्धारण की सुविधा दें। पारदर्शी वातावरण में उनके बीच आपसी बातचीत को प्रोत्साहित करें।
- प्रति – सहायिकाएं (क्रॉस-सब्सिडी), उपभोक्ताओं एवं अन्य लोगों द्वारा नैतिक निवेश, उचित मूल्य की दुकानों / पीडीएस में विशेष व्यवस्था, बाज़ार में आधारभूत संरचना जैसे उत्पादकों की कुछ लागतों के अवशोषण और / या उत्पादों के परिवहन के जरिए कम आय वाले परिवारों तक जैविक उत्पादों की पहुंच को सक्षम बनायें।
- जीएसटी और अन्य ऐसे करों को हटायें, जो हस्तशिल्प सहित शिल्पकारों द्वारा बनाये एवं हस्तनिर्मित उत्पादों के लिए अवसरों को और भी अधिक गैरबराबर बनाते हैं।
- उत्पादन की प्रक्रियाओं को देखने, समझने और उसमें भाग लेने तथा एक निष्क्रिय उपभोक्ता से बदलकर एक संवेदनशील भागीदार बनने के लिए सभी आयु वर्ग के शहरी उपभोक्ताओं का उन स्थानों का नियमित रूप से दौरा करने की व्यवस्था करें, जहां प्राथमिक स्तर के उत्पादक काम करते हैं।

फोटो सौजन्य श्रृष्टि बाजपेयी

फोटो सौजन्य झाडूराम हलमी और इजामसाइं काटेंगे

(बाएं) महाग्राम सभा; (दाहिने) ग्राम सभा निधि से राहत पैकेज पाने पर साले गाँव के निवासी

कोरची, महाराष्ट्र में वन आधारित आजीविका

उत्तरी गढ़चिरौली (महाराष्ट्र) में, 2016 में, 90 ग्राम–सभाओं ने एकसाथ मिलकर महाग्राम सभा (एमजीएस) नाम का एक संगठन बनाया। यह संगठन एक ऐसे मंच की जरुरत से निकला जो उनकी आजीविका को खतरे में डालने वाले खनन का कारगर प्रतिरोध कर सके और सुरक्षित स्थानीय आजीविका भी पैदा कर सके। एमजीएस प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर जोर देने, उत्पादन के साधनों को स्थानीय बनाने, जैव विविधता संरक्षण के जरिए पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने, सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने और लैंगिक असमानता जैसे सामाजिक संबंधों को बदलने की दिशा में काम कर रहा है। इस सबके जरिए वह अन्य बातों के साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा की पारंपरिक प्रणालियों समेत विकास के मौजूदा मॉडल पर सवाल उठा रहा है, खासकर इसलिए कि वे मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्र से जुड़े हैं।

वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम 1996 का उपयोग करते हुए, इनमें से 87 ग्राम सभाओं ने अपने वनों को प्रशासित करने, उनका उपयोग करने तथा उन्हें संरक्षित करने के अपने अधिकारों को हासिल किया है। यह कदम सदियों की केंद्रीकृत सरकारी नियंत्रण का विरोध करता है। इसके साथ, गैर-लकड़ी वन उपजों के संग्रह एवं व्यापार ने परिवार की आय और समुदाय-आधारित वन संरक्षण एवं प्रबंधन में

बढ़ोतरी की है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने ग्रामीण स्तर पर एक कोष की स्थापना को संभव बनाया है, जिसका उपयोग कई सामुदायिक गतिविधियों, मसलन जरूरतमंद परिवारों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करने और बाढ़ एवं सूखे से हुए नुकसान का सामना करने के लिए किया गया है। अच्छी कमाई करने वाली ग्राम सभाओं ने अन्य ग्राम सभाओं को वित्तीय उद्यम शुरू करने के लिए धन उधार दिया है।

कोविड के समय में, अपने जंगलों से कमाई करने की ग्राम सभा की क्षमता महत्वपूर्ण रही है। , कूकडेल, साल्हे, घणघटा और ज़ंकरगोंदी नाम के गांवों में, राशन के थैले वितरित किये गये हैं, जिसमें भूमिहीन परिवारों, विधवाओं, विकलांगता के शिकार लोगों एवं प्रवासी श्रमिक परिवारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

सबक

प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक प्रशासन के जरिए स्थानीय ज्ञान पर निर्भर रहते एवं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को स्थापित करते हुए आजीविका की सुरक्षा एवं पारिस्थितिक स्थिरता का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। भारत का आर्थिक एवं राजनीतिक मॉडल, जो केंद्रीकृत राज्य और निगमों के हाथों में सत्ता रखता है, इस मकसद के उलट है और इसमें बुनियादी बदलाव की जरुरत है।

संपर्क

सियाराम हलामी, 9420145861

इजामसाइं काटेंगे, 9422728937

फोटो सौजन्य मंजरी असोक

(बाएं) केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के कुदुम्बश्री सदस्य फेस मास्क उत्पादन करते हुए; (केंद्र में) केरल के कोल्लम जिले के कुदुम्बश्री सदस्य, सप्लाईको के लिए किराने की किट पैक करते हुए; (दाहिने) केरल के अलाप्पुझा जिले के मन्ननचेरी पंचायत के जनकिया होटल में कुडुम्बश्री के सदस्य पार्सल भोजन की व्यवस्था करते हुए

कुदुम्बश्री, केरल

वर्ष 1998 में केरल राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन के एक अंग के रूप में कुदुम्बश्री की शुरुआत की गयी। यह केरल में आस – पड़ोस की महिलाओं के समूहों का एक सामुदायिक संगठन है, जिसे महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से ग्रामीण एवं शहरी, दोनों, इलाकों में सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य जोर इस बात पर था कि गांव या नगरपालिका की प्रत्येक महिला सशक्तिकरण की इस प्रक्रिया का हिस्सा हो और इस प्रक्रिया का दायरा स्थानीय हो। सामुदायिक इंटरफ़ेस प्रदान करने और इस प्रकार स्थानीय स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सरकारी पहल, चाहे वो खाद्य सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य बीमा तक, आवास से लेकर उद्यमिता विकास तक, राष्ट्रीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम से लेकर जगराता समिति तक हो, और हर विकास का अनुभव कुदुम्बश्री पर निर्भर करता है। यह संगठन घरेलू वस्तुओं, कृषि-प्रसंस्करण एवं हस्तशिल्प सहित विभिन्न किस्म के उत्पादन को बढ़ावा देता है, जिससे लाखों महिलाएं अपनी बस्तियों में ही बैठकर अच्छी आजीविका कमाने में समर्थ होती हैं।

कोविड के इस काल में, कुदुम्बश्री सरकार के राहत कार्यों एवं समुदायों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में उभरा है। स्थानीय स्वशासन के साथ मिलकर कुदुम्बश्री ने स्थानीय निकायों में सामुदायिक रसोई की शुरुआत की, जहां भोजन तैयार किया जा रहा है और उस तैयार भोजन को होम क्वारंटीन के तहत रखे गये व्यक्तियों एवं जरूरतमंद लोगों को उनके घर पर वितरित किया जा

रहा है। इस सामुदायिक संगठन ने गांव के साथ – साथ शहरों में भी कोविड से जुड़ी जागरूकता, सरकारी निर्देशों, हेल्पलाइन के जरिए लोगों को जोड़ने आदि के बारे में सूचनाओं के प्रसार में बेहद सक्रिय भूमिका निभायी है। कुदुम्बश्री ने लगभग 300 सिलाई केन्द्रों के जरिए 20 लाख से भी अधिक कपड़े के मास्क तैयार किये एवं बेचे हैं। यही नहीं, 21 लघु – उद्यम इकाइयों ने लगभग 5000 लीटर सेनीटाईज़र तैयार किये हैं। कोविड – 19 के माहौल में, कुदुम्बश्री कोविड -19 के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले फेस - शील्ड तैयार कर रहा है।

सबक

स्वशासन एवं समुदायों का सशक्तिकरण, महिलाओं का सशक्तिकरण, समुदाय द्वारा संचालित प्रयासों की शुरुआत आदि एक अहम भूमिका निभा सकती है। जैसाकि हम वर्तमान संकट के दौरान देख सकते हैं, आफत के समय में निर्णय लेने एवं नियंत्रण की केंद्रीकृत व्यवस्था शायद ही कभी काम आती है। चुनौतियों से निपटने के लिए हरेक राज्य को अपने नियम एवं प्रक्रिया बनानी होगी और आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। निर्णय लेने की प्रक्रिया जितनी विकेंद्रीकृत एवं सशक्त होगी, संकटों से निपटने में हम उतना ही समर्थ होंगे।

संपर्क

ed@kudumbashree.org, 0471-2554717

फोटो सौजन्य मंजरी असोक

(बाएं) केरल के पठानमथिट्टा जिले के आदिवासी क्षेत्रों में भोजन किट वितरण; (केंद्र में बाएं) केरल के पठानमथिट्टा जिले के कुदुम्बश्री सदस्य फेस मास्क उत्पादन में करते हुए; (केंद्र में दाहिने) केरल के कोझिकोड जिले की कुदुम्बश्री महिलाएं सैनिटाइजर उत्पादन करते हुए; (दाहिने) फ्लोटिंग सुपरमार्केट केरल के अलाप्पुझा जिले के कानाकारी पंचायत सीडीएस द्वारा व्यवस्थित किया गया है

फोटो सौजन्य समाज प्रगति सहयोग

(बाएं) मिट्टी का बांध निर्माण; (दाहिने) सेवनपंती नाला जल प्रबंधन के परिणाम

मध्य भारत में आजीविका एवं पानी की सुरक्षा

समाज प्रगति सहयोग (एसपीएस) भारत के नागरिक समाज द्वारा शुरू की गयी बड़ी पहलों में से एक है। इसका मुख्यालय मध्यप्रदेश के देवास में है। यह संगठन अपने सहयोगियों के साथ मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के 72 जिलों में लाखों एकड़ जमीन पर काम करता है। सुरक्षित खेती एवं अन्य आजीविका के लिए आधार के तौर पर विकेंद्रीकृत जल सुरक्षा को प्राथमिकता बनाते हुए पिछले तीन दशकों में इस संगठन का अधिकांश काम आदिवासी समुदायों पर केन्द्रित रहा है। समानता, स्थिरता, सशक्तिकरण, महिलाओं समेत सबसे कमजोर लोगों को प्राथमिकता देना इसके मुख्य सिद्धांत हैं।

इस संगठन के कार्यों के कुछ अहम परिणामों में लगभग 120 गांवों में पीने एवं सिंचाई के पानी के मामले में आत्मनिर्भरता और संगत कृषिगत उत्पादकता में तेज उछाल शामिल है, जिससे संकटजनित पलायन में 80% की कमी आई। आजीविका, कृषि (खेती एवं पशुपालन) एवं सहायक गतिविधियों से जुड़े इसके अन्य कार्य सैकड़ों गांवों में फैले हैं। कुल 120 से अधिक गांवों में, 9000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर कीटनाशक रहित खेती को बढ़ावा दिया गया है। इन कार्यों का संगठनिक आधार कुल 500 से अधिक गांवों एवं 15 शहरों (वर्ष 2018 के अंत तक) में गठित महिलाओं की स्वयं – सहायता समूहों (एसएचजी) हैं। इसका एक अन्य सांस्थानिक हस्तक्षेप राम रहीम प्रगति प्रोड्यूसर कं। लि। (आरआरपीपीसीएल) है। कुल 300 से अधिक स्वयं – सहायता समूहों की 4800 महिलाएं इसकी सदस्य हैं। पूरे कार्यक्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता एवं सुधार भी इसका एक अहम फोकस है।

सीधी भागीदारी के अलावा, यह संगठन अन्य क्षेत्र के लोगों को अपने बाबा आम्टे सेंटर फॉर पीपुल्स एम्पावरमेंट के जरिए सीखने का अवसर भी प्रदान करता है।

कोविड संकट के दौरान, एसपीएस ने मध्य प्रदेश के देवास एवं खरगोन जिलों में कुल 13,000 से अधिक परिवारों को राहत पहुंचायी है। इस कार्य में स्वयं – सहायता समूह मुख्य रूप से सबसे लाचार लोगों की पहचान करने एवं राहत पैकेजों के वितरण में संलग्न हैं। एक दिलचस्प नयी बात यह थी कि इस पैकेज के लिए आरआरपीपीसीएल के जरिए से हजारों स्थानीय किसानों से गेहूं की खरीद की गई। इससे लॉकडाउन के दौरान इन किसानों को संकट के दबाव में बिक्री करने से बचने में मदद मिली। आरआरपीपीसीएल द्वारा इस गेहूं को आटा में बदला गया और 38 लाख रुपए की लागत वाले इस 118।40 टन आटे को राहत पैकेज में शामिल किया गया। इस प्रकार, तिहरे लक्ष्य को हासिल किया गया : एक अच्छी दर पर गेहूं की खरीद के जरिए किसानों को सहयोग, गेहूं के आटे की बिक्री के जरिए आरआरपीपीसीएल के किसान शेयरधारकों को आमदनी और आवश्यक वस्तुओं के पैकेज की मुफ्त आपूर्ति के जरिए सबसे कमजोर परिवारों को राहत।

एसपीएस को अपने अगले चरण में आर्थिक संकट के विरुद्ध एक दीर्घकालिक रणनीति के तौर पर स्थानीय आजीविका को और अधिक मजबूत करने की उम्मीद है।

सबक

स्वयं – सहायता संस्थानों, खासकर महिलाओं पर केन्द्रित, के जरिए गांवों का सशक्तिकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था का पुनरोद्धार, जोकि संकट के दबाव में काम की तलाश में पलायन को कम करता है, संकट के समय में समुदायों को जबरदस्त लचीलापन प्रदान करता है। इसमें राज्य के राहत संबंधी उपायों से तुलनात्मक आज़ादी शामिल है।

संपर्क

मिहिर शाह, mihirbhai25@gmail.com

फोटो सौजन्य समाज प्रगति सहयोग

(बाएं) समाज प्रगति सहायता (एसपीएस) COVID-19 संकट से राहत कार्य; (दाहिने) हाटपिपलिया महिलाओं की एसएचजी फेडरेशन (एसपीएस) जनरल बॉडी मीटिंग

फोटो सौजन्य खोज

(बाएं) राहु ग्राम सभा; (दाहिने) राहु गाँव, अमरावती जिला, महाराष्ट्र में बाँस डिपो

वन अधिकारों से लैस गांव, मेलघाट क्षेत्र, महाराष्ट्र

वनाधिकार कानून 2006 के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार (सीएफआर) हासिल करने के बाद महाराष्ट्र के अमरावती जिले में मेलघाट की पहाड़ियों की तराई में स्थित पेविहीर एवं अन्य गांवों ने अपने वनों के संरक्षण एवं बेकार हो गयी भूमि के दोबारा वानिकीकरण में महारत हासिल किया है। उनके ग्राम – सभाओं ने मनरेगा, डेयरी एवं मछलीपालन जैसे स्रोतों से आमदनी बढ़ाने तथा जैविक खेती के चलन को और अधिक अपनाने के लिए विभिन्न सरकारी एवं नागरिक समाज की एजेंसियों के साथ समन्वय किया है। लोगों ने स्थानीय बांधों की उड़ाही कर उससे गाद निकाला और उस गाद को खेतों में इस्तेमाल किया, जिससे उनकी उत्पादकता लगभग 3 से 4 गुणा बढ़ गयी। बेहतर संरक्षण ने वन्यजीवों के प्राकृतिक वास में भी बढ़ोतरी की है।

कोविड संकट के दौरान, पेविहीर ने तत्काल अपनी सीमाओं को बंद कर दिया, विक्रेताओं के साथ साप्ताहिक आधार पर आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का बंदोबस्त किया और यह सुनिश्चित किया कि खेतों में किये गये कामों के लिए किसानों को समय पर पारिश्रमिक मिले। उन्होंने अपने अन्य कार्यों को कुछ इस तरीके से पुनर्निर्धारित किया कि उन्हें न तो कृषि और न ही वानिकीकरण के कार्यों के लिए बाहर के श्रमिकों की जरूरत थी। लिहाज़ा लॉकडाउन के दौरान अधिकांश समय खेतों एवं जंगलों में काम जारी रहा। महिलाओं ने अपने स्वयं – समूह (एसएचजी) के जरिए मास्क तैयार किया और एक अन्य एसएचजी ने यह सुनिश्चित किया कि पीडीएस की आपूर्ति समय पर सभी परिवारों तक पहुंचे। गांव में आना और जाना व्यवस्थित रूप से दर्ज है।

राहु नाम के एक अन्य गांव ने इस स्थिति से अपेक्षकृत बेहतर तरीके से निपटा। वजह, इसने ठीक उसी समय गैर-लकड़ी वन उपज (विशेष रूप से बांस और तेंदू के पत्ते) से प्राप्त राजस्व को प्रत्येक परिवार के बीच 10,000 रुपये के हिसाब से वितरित किया था। यह इसलिए भी संभव हुआ क्योंकि वनाधिकार कानून (एफआरए) के तहत सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) अधिकार ने पिछले 5 वर्षों से राहु को अपने वनों का प्रबंध करने में समर्थ बनाया है, जिससे 3 करोड़ रूपए से अधिक की कमाई हो रही है। इस कमाई का उपयोग ग्राम सभा में तय किये गये सामूहिक सामुदायिक गतिविधियों के साथ - साथ वनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं विकास पर भी किया जाता है।

कोविड के दौरान राहु ने भी अपनी सीमाएं बंद कर दी और एक स्थानीय ग्रामवासी के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति का बंदोबस्त किया। इस गांव के लोगों ने अपनी खेती की जमीन पर काम करना जारी रखा और बांस एवं महुआ के फसल की कटाई की तैयारी भी शुरू की। इस साल, लगभग 100 परिवारों के पास 1 क्विंटल महुआ फूलों का संग्रह है। ग्राम सभा इसे लोगों से खरीदने, उसका भंडारण और बाद में विपणन करने पर विचार कर रही थी ताकि संकट के दबाव में की जाने वाली किसी भी बिक्री को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने स्थानीय बैंकों की सेवाओं का भी इस्तेमाल किया। बांस के फसल की कटाई और फिर एक खुली नीलामी के जरिए उसकी बिक्री करने के लिए उनके पास अभी पूरे एक महीने का समय है। बाज़ार के रवैये को लेकर एक चिंता जरुर है, लेकिन उन्हें विश्वास है कि कोई न कोई रास्ता जरुर निकलेगा।

सबक

स्थानीय एकजुटता एवं प्रशासन और एफआरए जैसे उपयुक्त कानूनों के जरिए खुद का सशक्तिकरण करने वाले गांव कोविड जैसे संकटों से बेहतर तरीके से निपटने में अन्य गांवों एवं शहरों के मुकाबले ज्यादा सक्षम हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका लचीलापन दिखाई देता है। उपयुक्त डिजिटल तकनीक (मसलन आवश्यक सेवाओं के संबंध में संवाद के लिए और स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए) का उपयोग भी बेहद अहम है।

संपर्क

पूर्णिमा उपाध्याय, khojmelghat@gmail.com
07223-277292/9890359154/9422917732
रामलाल, gramsabhapayvihir@gmail.com
7774877304

फोटो सौजन्य इलांगो आर.

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

(बाएं) कुथूमबक्कम समुदाय की बैठक; (दाहिने) समथुवपुरम घर और दुकान, कुथूमबक्कम, तमिलनाडु

तमिलनाडु के कुथूमबक्कम में आर्थिक पुनरुत्थान

कुथूमबक्कम, चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित एक गांव है। यहां कुल सात टोले हैं। 1990 के दशक से पहले तक, कुथूमबक्कम में सड़कें या आधारभूत संरचनाएं नदारद थीं, आजीविका असुरक्षित थी, वहां व्यापक जातिगत भेदभाव था, और महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती रहती थीं। यह इलाका अवैध अरक (शराब) और कालाबाजारी एक बड़ा क्षेत्रीय अड्डा था।

ऐसी ही एक परिस्थिति में इलांगो रंगास्वामी ने, एक शहर - आधारित नौकरी छोड़कर कुथूमबक्कम लौटने और 1996 में पंचायत चुनाव जीतने के बाद, गांव के कायाकल्प के लिए प्रयास करने का निर्णय किया। उसने जमीनी स्तर पर योजना निर्माण का समावेश किया और स्थानीय लोगों को गांव की समस्याओं के बारे में सक्रिय होने के लिए एकजुट किया। उसकी शुरुआती अपेक्षाएं अवैध शराब के उत्पादन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जातिगत भेदभाव की समस्याओं से निपटने की थीं। उसका बड़ा लक्ष्य सबके लिए आवास उपलब्ध कराना, अधिक से अधिक स्वयं – सहायता समूहों का निर्माण करना, पंचायत की गतिविधियों के जरिए रोजगार का सृजन करना, स्थानीय संसाधनों पर आधारित आजीविका तैयार करना, और अभाव के बजाय प्रचुरता के सिद्धांत पर एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था। लगभग 150 परिवार लघु स्तर की उत्पादक इकाइयों में स्थानीय रुप से रोजगार हासिल करने में समर्थ हुए। इसके अलावा, राज्य सरकार की एक आवासीय योजना (समथापुरम) का इस्तेमाल करके वह दर्जनों परिवारों को मिलीजुली जातियों की एक आवासीय कालोनी में रहने के लिए समझाने में कामयाब रहा। इस आर्थिक पुनरुद्धार का एक नतीजा यह रहा कि काम के लिए बाहर पलायन कम हो गया।

एक इंजीनियर और आविष्कारक होने के नाते, इलांगो ने सार्वजानिक स्थानों एवं घरेलू उपयोग, दोनों, के लिए उचित दाम वाली एक सौर - उर्जा किट समेत उर्जा की बचत के उपायों पर काम किया। अच्छे व्यवहारों के प्रसार एवं तमिलनाडु के पंचायत नेताओं को शिक्षित करने और उनमें

क्षमता विकसित करने के लिए पंचायत अकादमी नाम की एक परियोजना शुरू की गयी। इन सबके जरिए, अधिकतम स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उसने गांव के भीतर लगातार संवाद जारी रखा। इलांगो कहते हैं कि प्राथमिक कार्य "परिवार के स्तर पर और परिवारिक स्तर के बस्तियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में कौशल स्तर का निर्माण करना है, ताकि गांव आत्मनिर्भर बनें। ऐसे गाँवों का नेटवर्क आत्म-सूचित और विश्वसनीय आर्थिक क्षेत्र तैयार करेगा।

कोविड – 19 के जवाब में, इलांगो ने सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए कीटाणुनाशक बनाने का एक तरीका तैयार किया है, जिसे किसी भी बस्ती में स्थापित किया जा सकता है। कीटाणुनाशक एवं अन्य सैनिटरी उत्पादों का उत्पादन करने के लिए समुदाय इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं और पूर्ण स्थानीय स्वच्छता सुनिश्चित कर सकते हैं।

सबक

लघु उद्यम गांवों और कस्बों में स्थानीय आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हो सकते हैं। इसके अलावा, जातिवाद को कम करने के लिए संघर्ष और अभिनव तरीके अहम हैं। इस तरह के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के जरिए, ग्रामीणों को रुके रहने और सम्मानजनक जीवन एवं आजीविका के लिए सक्षम करने वाली स्थितियां संकट की वजह से होने वाले पलायन को कम कर सकती हैं।

संपर्क

इलांगो आर., panchayatgovt@gmail.com, 9940682201

इलांगो के साथ कोविड – काल संवाद के लिए भी देखें:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/05/vikalp-varta-4-innovation-and.html

फोटो सौजन्य : स्पेशल अरेंजमेंट (द हिन्दू)

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

(बाएं) COVID समय में इलांगो आर. द्वारा सौर निस्संक्रामक प्रक्रिया का आविष्कार किया गया; (दाहिने) विनिर्माण इकाई, कुथूमबक्कम, तमिलनाडु

फोटो सौजन्य अशीष कोठारी

(बाएं) मास्टर बुनकर शामजी विश्राम सीजू और युवा खराड़ बुनकर दमाभाई मारवाड़ा, कच्छ; (केंद्र में) प्रकाश नरनभाई वानकर, नए नवाचारों के साथ कालीन बुनाई की पुश्तैनी परंपरा को जारी रखते हुए, कच्छ; (दाहिने) शीतल हितेशभाई, कई युवा महिलाओं में से एक, जो अब गाँव जामथड़ा बुनती है

कच्छ में हथकरघा बुनाई का पुनरुद्धार

जैसाकि भारत में आम तौर पर शिल्प के साथ होता है, लगभग दो दशक पहले कच्छ में हथकरघा शिल्प एवं व्यापार में जबरदस्त गिरावट थी। सस्ते एवं बड़े पैमाने पर उत्पादित औद्योगिक विकल्पों के आगमन और पिछले 1990 के दशक एवं 2000 के दशक की शुरुआत में प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला के कारण, यह व्यवसाय अपने अतीत की छाया मात्र रह गयी थी। इसके कुछ ही समय बाद, तबाही के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण के नागरिक समाज के एक गहन प्रयास के रूप में, एक शिल्प सुविधा संगठन खमीर ने कुछ उद्यमी बुनकरों के साथ मिलकर हथकरघा बुनाई को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। स्वदेशी का अभिनव प्रयोग करते हुए, जैविक रूप से उगाए गए कला कपास की खेती और खेती से कपड़ा उत्पादन की श्रृंखला को फिर से स्थापित करते हुए, उन्होंने नए उत्पादों की एक श्रृंखला तैयार की जो बाजार को आकर्षित कर सकें। कुछ वर्षों के भीतर यह शिल्प पुनर्जीवित हो गया, और अब भारत के भीतर और बाहर एक स्थापित नाम है।

इसके नतीजे में लोगों के समग्र कल्याण, विशेषकर आर्थिक, में चौतरफा बढ़ोतरी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इसने युवाओं को या तो इस पेशे में बने रहने या फिर उद्योगों अथवा मध्य-पूर्व एशिया में काम करने के बाद, इसमें वापस लौटने के लिए आकर्षित किया है। इसके पीछे उनकी प्रेरणा सिर्फ वित्तीय नहीं है। बल्कि खुद की रचनात्मकता को व्यक्त करने, घर से काम करने में सक्षम होने एवं अपने परिवार के साथ रहने, खुद का मालिक होने और अपनी पैतृक विरासत को जारी रखने की संतुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कच्छ के

वनात के मूलतत्व को खोये बिना अभिनव प्रयोग एवं रचनात्मकता, और ज्ञान एवं सीखने की प्रणालियों के संकर का फलना – फूलना यहां ध्यान देने योग्य है।

इससे सामाजिक संबंधों में एक बदलाव भी जुड़ा रहा है। इस बदलाव में जाति (परंपरागत रूप से सामाजिक वर्णक्रम में सबसे निचले पायदान पर माने जाने वाले समुदाय के प्रति जातिवाद में कमी), लिंग (महिलाओं के लिए एक बड़ी भूमिका और आवाज) और पीढ़ियां (बुजुर्गों के लिए पारंपरिक सम्मान को बनाए रखते हुए युवाओं के बीच अपेक्षाकृत अधिक मुखरता) भी शामिल है।

यो तो इस शिल्प के उत्पाद अब एक राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार (पारंपरिक रूप से यह ज्यादातर स्थानीय विनिमय के लिए था) की ओर मुखातिब हैं, इस बदलाव ने इसे और अधिक नाजुक भी बना दिया है। कोविड संकट के दौरान, वैश्विक व्यापार के उतार-चढ़ाव के प्रति इसकी नाजुकता तीखे तरीके से स्पष्ट हो गई है। इससे कम संपन्न बुनकरों, मसलन 'नौकरी करने वाले मजदूर' जो 'उद्यमी' कहलाने वाले बुनकरों के लिए उत्पादन करते हैं, के प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि, कुल मिलाकर, वनकर समुदाय को यह लगता है कि वह पिछले संकटों से उबर गया है और इस संकट से भी प्रथागत अनुकूलन और अभिनव प्रयोगों के सहारे उबर जायेगा।

सबक

पर्याप्त अभिनव प्रयोगों एवं निवेश के सहारे पारंपरिक शिल्प व्यवसाय समर्थ, जीविकोपार्जन के सम्मानजनक स्रोत हो सकते हैं, ताकि युवा पीढ़ियां इसमें बने रह सकें या यहां तक कि इसमें वापस भी आ सकें। नई तकनीकों और डिजाइनों की खोज करते हुए और भेदभाव या असमानता के पारंपरिक या नए रूपों से निपटते हुए भी स्थानीय ज्ञान, रचनात्मकता और उद्यमशीलता के सहारे आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। इस किस्म के व्यवसाय महज एक रोजगार नहीं हैं, बल्कि ऐसी आजीविका हैं जो जीवन के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं के साथ आर्थिक पहलू को जोड़ती हैं।

संपर्क

घटित लहेरू, ghatit.laheru@khamir.org, 9979450131

युवा बुनकरों के साथ कोविड – काल संवाद भी देखें:
https://vscoronatimes.blogspot.com/2020/04/vikalp-varta-2-youth-weave-new-story-in.html

ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की असुरक्षा की वजह से बाहर की ओर होने वाले पलायन के बारे में सिफारिशें

- वनवासियों, मछुआरों, पशुपालकों, शिल्पकारों और अन्य ऐसे उत्पादकों को प्राथमिकता देते हुए स्थानीयकृत आजीविका और स्थानीय बाजारों को बढ़ावा दें।
- उन स्थायी प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित आजीविका और पारिस्थितिक तंत्रों एवं पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दें, जिनपर वे निर्भर हैं।
- आत्मनिर्भरता एवं स्वशासन, ग्राम सभाओं, मुहल्ला सभाओं तथा अन्य स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की इकाइयों के सशक्तिकरण को बढ़ावा दें। महिलाओं एवं अन्य कमजोर वर्गों / लोगों की पूर्ण भागीदारी को अधिकतम प्राथमिकता दें।
- पारदर्शिता, सामुदायिक लाभ तथा बारी – बारी से नियंत्रण के उचित नियमों के साथ एक ग्राम निधि के निर्माण को सक्षम बनायें।
- कार्यक्रमों और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्थानीय प्रशासन, नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दें।
- वन अधिकार अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम व पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार) अधिनियम, और नरेगा जैसे कानूनों के कार्यान्वयन को समर्थन दें। इन कार्यक्रमों को उनके साथ जोड़ें जो आत्मनिर्भरता और स्व-शासन का लक्ष्य हासिल करने के लिए समुदायों के वास्ते दीर्घकालिक स्थानीय संसाधन और क्षमता का निर्माण करते हैं।
- बुनियादी जरूरतों के लिए लंबी दूरी वाले बाजार पर निर्भरता को प्रोत्साहित करने या मजबूर करने वाली नीतियों एवं कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से बंद करें।
- विकास की उन सभी गतिविधियों एवं नीतियों की समीक्षा करें जिनमें प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का अपरिवर्तनीय विनाश का समवेश है।
- बड़े उद्योगों को उन सभी उत्पादों और सेवाओं के लिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन और सहायता को हटा दें, जोकि स्थानीय समुदायों और विकेन्द्रीकृत संस्थाओं के जरिए उत्पादित और आदान-प्रदान / वितरित किये जा सकते हैं।
- उन उत्पादों के मशीन उत्पादन के लिए दिए जाने वाले प्रोत्साहन को हटा दें, जो श्रम आधारित तरीकों के जरिए उत्पादित किए जा सकते हैं।
- लोगों के बुनियादी अधिकारों तथा प्रकृति एवं पर्यावरण के संरक्षण को सुरक्षित रखने वाले कानूनों को कमजोर करना या लचीला करना या उनसे बचकर निकल लेना बंद करें।
- हस्तनिर्मित उत्पादों और प्रक्रियाओं पर अनुचित कराधान, लेवी, आदि (जैसे जीएसटी) को रोकें। उत्पादकों को केवल सरकारी एजेंसियों को बेचने के लिए मजबूर न करते हुए सभी कृषि / वन / मत्स्य उत्पादन और हस्तशिल्प के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करें।

समस्या : स्वास्थ्य संकटों से निपटने में असमर्थ समुदाय

समाधान: सामुदायिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण

फोटो सौजन्य कुनारिया पंचायत

(बाएं) कुनारिया ग्राम सभा; (दाहिने) कुनारिया में गाँव की मैपिंग, कच्छ, गुजरात

पंचायत की अगुवाई में कुनारिया, कच्छ, गुजरात में कोविड के खिलाफ कदम

कुनारिया गांव कच्छ में भुज से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पिछले कुछ सालों में इस गांव ने सक्रिय रूप से 73 वें संविधान संशोधन, जो गांवों के स्व-शासन को बढ़ावा देता है, के प्रभावी कार्यान्वयन की ओर अपना कदम बढ़ाया है। वर्ष 2017 में चुने गए गांव के वर्तमान सरपंच सुरेश छंगा ने अधिक से अधिक सार्वजनिक भागीदारी, सामूहिक निर्णय, सरकार की प्रासंगिक योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और ग्रामीणों एवं सरकारी विभागों के बीच की खाई को पाटने को प्रोत्साहित किया है।

योजनाओं, नीतियों और बजट के बारे में प्रासंगिक जानकारी, नियमित बैठकों और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनके जीवन पर सीधा असर डालने वाले मुद्दों पर उनकी भागीदारी एवं जागरूकता बढ़ने के साथ – साथ शासन की पारदर्शिता बढ़े। महिलाओं की भागीदारी को शून्य से बढ़ाकर 50% तक करते हुए उनकी आवाज़ और राय को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसे प्रगतिशील कानूनों को लागू करने के बारे में भी पंचायत सक्रिय रही है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रयास किया गया है।

कुनारिया ने इलाके की अन्य पंचायतों को जोड़ने का काम भी किया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशुपालन, महिलाओं की भागीदारी, स्वच्छता, रोजगार एवं पर्यावरण के मसले पर 16,000 लोगों के बीच 115 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

समस्या : स्वास्थ्य संकटों से निपटने में असमर्थ समुदाय

समाधान: सामुदायिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण

उदहारण 01 | उदहारण 02 | सिफारिशें

कोविड संकट के दौरान, इस पंचायत ने कोविड एवं प्रासंगिक सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का पूरा उपयोग किया और घर-घर स्वास्थ्य सर्वेक्षण को संभव बनाया। आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए सिर्फ निर्धारित व्यापारी / उत्पादक ही गांव में प्रवेश कर सकते थे। लगभग 316 जरूरतमंद परिवारों को पंचायत की ओर से भोजन की सहायता प्रदान की गई। अपेक्षाकृत संपन्न परिवारों एवं कई किसानों ने एक महीने तक 87 सबसे गरीब परिवारों को खिलाने में योगदान दिया। दृष्टिबाधित एवं शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों, एकल-महिलाओं तथा हाशिए पर के अन्य परिवारों को भोजन, आवश्यक दवाएं तथा अन्य बेहद जरूरी एवं बुनियादी जरूरतों के सामन मुहैया कराये गये। 106 मजदूरों को तत्काल स्थानीय प्रशासन के साथ परामर्श से मनरेगा के जरिए काम उपलब्ध कराया गया।

सबसे नवीन कदमों में से एक था, घर में फंसे बच्चों को संगीत, शिल्प, खाना पकाने, पारंपरिक तकनीकों के विशेष कौशल सिखाने के लिए बुजुर्गों से संपर्क करना और साथ ही ई-लर्निंग को संभव बनाना। ऐसा करने के पीछे कारण इस बात को रेखांकित करना था कि बच्चे घरों में ऊब रहे थे, उन्हें स्कूल की याद सता रही थी और कुछ मामलों में उन्हें घरों में पड़े हुए बुजुर्गों की आक्रामकता का भी सामना करना पड़ रहा था।

यदि भविष्य में, कोविड के मामले सामने आते हैं, तो पंचायत के पास आपात स्थिति के लिए अलग से निर्मित एक वार्ड रखने की योजना है।

संपर्क

सुरेश छंगा, sureshchhanga@gmail.com, 9913055305

फोटो सौजन्य कुनारिया पंचायत

(बाएं) कोविड के दौरान मास्क वितरण; (दाहिने) आपदा प्रबंधन समिति के साथ बैठक

समस्या : स्वास्थ्य संकटों से निपटने में असमर्थ समुदाय
समाधान: सामुदायिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण

फोटो सौजन्य ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव

टीएचआई ने मृत्यु दर में कमी लाई है और बच्चों में कुपोषण के स्तर में 70% की कमी आई है

तमिलनाडु के सित्तीलिंगी में कोविड के खिलाफ स्वास्थ्य की दृष्टि से सशक्त पंचायत की त्वरित प्रतिक्रिया

ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव (टीएचआई) एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के सित्तीलिंगी गांव में स्थित है। यह इस इलाके में स्थानीय समुदाय, मालेवासी आदिवासियों, के कल्याण के लिए काम करता है। टीएचआई की स्थापना 1993 में केरल के एक युवा डॉक्टर दम्पति रेगी जॉर्ज, जोकि एक एनेस्थिसियोलॉजिस्ट थे और ललिता रेगी, जोकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, द्वारा की गई थी। यह दम्पति गांधीवादी मूल्यों से प्रेरित था। इस परियोजना की शुरुआत एक क्लीनिक और लेबर रूम के रूप में मिट्टी से बनी सिर्फ एक झोपड़ी से हुई थी। और अब यह एक आईएसओ से प्रमाणित अस्पताल बन गया है, जिसमें छह डॉक्टर और 30 नर्स हर वर्ष 1 लाख मरीजों को देखते हैं।

स्थानीय लोगों के सहयोग से उनके निरंतर प्रयासों की बदौलत इस पहल ने 1993 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 157 से घटाकर प्रति 1000 पर लगभग 20 कर दिया है। पिछले एक दशक में मातृ मृत्यु दर का कोई मामला सामने नहीं आया और बच्चों में कुपोषण के स्तर में 70 प्रतिशत की कमी आई है। टीएचआई का फोकस सिर्फ स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। इसने एक सामुदायिक पहुंच (आउटरीच) कार्यक्रम, सामूहिक जैविक खेती और शिल्प से जुड़ी एक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य लैम्बडी कढ़ाई को पुनर्जीवित करना है। इसने महिला उद्यमियों को जुटाने के लिए भी एक कार्यक्रम शुरू किया है।

समस्या : स्वास्थ्य संकटों से निपटने में असमर्थ समुदाय

समाधान: सामुदायिक स्वास्थ्य सशक्तिकरण

समुदाय को एकजुट करने के उनके मॉडल ने क्षेत्र में स्थानीय शासन को भी मजबूत किया है और कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए सित्तीलिंगी पंचायत की त्वरित प्रतिक्रिया एक आदर्श उदाहरण है। जिस समय महामारी की घोषणा की गई, पंचायत अध्यक्ष सुश्री मधेश्वरी ने पीएचसी, टीएचआई और अन्य सरकारी विभागों के सदस्यों के साथ एक जरूरी बैठक बुलाई और आपदा को नियंत्रण करने वाला अंदाज़ अपनाने में जुट गयीं।

इस पंचायत (लगभग 15,000 की जनसंख्या के बीच) के तहत आने वाले गांवों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए गए और इसके बारे में ऑटोरिक्शा से लगातार घोषणाएं की गईं। सार्वजनिक जगहों पर जहां लोग इकट्ठा होते हैं वहां सामाजिक दूरी का पालन करवाया गया और किराना की दुकानों और होटलों को छोड़कर सभी दुकानें बंद कर दी गई। वापस लौटकर आने वाले प्रवासी क्वारंटीन किये गये और अस्पताल ने उनके लिए अलग से ओपीडी शुरू की। आमदनी सृजन के एक पहल के रूप में स्थानीय दर्जियों से ग्रामीणों के लिए थोक में मास्क तैयार करने के लिए कहा गया। राशन वितरण में भीड़-भाड़ न हो, इसके लिए टोकन प्रणाली को शुरू किया, और कुछ इलाकों में हाथ धोने के नियमों का पालन न करने पर जुर्माना लगाया गया। सोशल मीडिया के जरिए दैनिक जानकारी देने-लेने की व्यवस्था बनाई गई।

सबक

वे समुदाय जो स्व-शासन के लिए सशक्त हैं और स्वास्थ्य से संबंधित अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण करने में सक्षम हैं, कोविड जैसे संकटों के साथ - साथ अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी मुद्दों से भी बेहतर तरीके से निपट सकते हैं । इस तरीके से बाहरी विशेषज्ञता पर निर्भरता को कम से कम किया जा सकता है, जिससे केंद्रीयकृत सुविधाओं और कर्मियों पर बोझ भी कम होगा।

संपर्क

रेगी और ललिता, regilalitha@gmail.com / thisittilingi@gmail.com, 9585899061, 9488344325

स्वास्थ्य एवं अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए स्थानीय क्षमता के लिए सिफारिशें

- स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाएं (पीएचसी आदि) को मजबूत बनाने और उनकी स्थापना को सुनिश्चित करें। संबंधित सरकारी विभागों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के समग्र शासन के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं की विविध प्रणालियों को एकीकृत करें। सब्सिडी के सिद्धांत का उपयोग करें यानी कि स्थानीय स्तर पर जो कुछ भी किया जा सकता है, वह होना चाहिए और इसके अलावा ब्लॉक/जिला/राज्य स्तर की सुविधाएं केवल विशिष्ट सेवाएं होनी चाहिए।
- सभी तरह की सूचना के प्रवाह और पारदर्शिता (योजनाएं/कार्यक्रम, नियम/कानून, संकट के लिए आपातकालीन उपाय) के लिए पारम्परिक और नये सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग करने के लिए स्थानीय स्व-शासन के संस्थानों को सक्षम बनायें।
- इस तरह के संस्थानों में सभी कमजोर परिवारों/व्यक्तियों और उनकी विशिष्ट जरूरतों के बारे में एक अद्यतन (तालिका) रोस्टर होना चाहिए।
- महिलाओं और बच्चों के विचारों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करें।
- सभी संबंधित सरकारी कर्मचारियों के विभागीय सीमा से उबरते हुए उनके बीच, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय स्व-शासन संस्थानों के साथ समन्वय को संभव बनायें।
- स्वास्थ्य, भोजन, पोषण, आजीविका (कृषि, शिल्प, उद्यमिता) पर समग्र रूप से समझ एवं नियोजन और कार्रवाई को संभव बनायें।
- कला, संगीत, नृत्य, बुनियादी स्वास्थ्य और हर किसी के लिए स्वच्छता को मिलाकर जीवन के जरिए और जीवन भर के लिए सीखने और शिक्षा के साथ प्रयोग करें।

इस दस्तावेज में अनंतू, सृष्टि बाजपेयी, सेतुलक्ष्मी विनयन, पूर्णिमा उपाध्याय, संगीता श्रीराम, इश्तियाक अहमद, एलेक्स जेन्सेन, सुजाता पद्मनाभन, इलंगो रंगास्वामी, सुजीत सिन्हा, मिहिर शाह, अदिति सजवान, सुरेश छंगा, गिज्स स्पूर, जूही पांडे, गोपी शंकरसुब्रमणि की सूचनाओं (इनपुट्स) को एक साथ रखा गया है और आशीष कोठारी द्वारा समन्वित किया गया है। जितेंद्र कुमार द्वारा हिंदी अनुवाद और नवीद दादन द्वारा डिजाइन और लेआउट किया गया है।

उद्धरण: विकल्प संगम, कोविड – 19: हाउ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क ऑफ़ आर्डिनरी पीपल कैन शो अस पाथवेज आउट ऑफ़ द क्राइसिस – वॉल्यूम 1, विकल्प संगम कोर ग्रुप, पुणे, मई, 2020

यह एक कॉपीलेफ्ट प्रकाशन है। यह गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए स्वतंत्र रूप से पुन: पेश किया जा सकता है, बेहतर हो कि श्रेय एवं उद्धरण के साथ, और कोई भी पुनर्प्रकाशन समान शर्तों के साथ और बिना किसी कॉपीराइट के होना चाहिए।

विकल्प संगम मानव और पारिस्थितिक कल्याण के लिए न्यायसंगत, समतापूर्ण और टिकाऊ रास्ते पर काम करने वाले आंदोलनों, समूहों और व्यक्तियों को एक साथ लाने का एक मंच है। यह विकास के वर्तमान मॉडल और इसकी असमानता और अन्याय की संरचनाओं को खारिज करता है, और व्यवहार एवं दृष्टिकोण में विकल्पों की खोज करता है। देश भर में लगभग 60 आंदोलन और संगठन इसके कोर ग्रुप के सदस्य हैं।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें : http://www.vikalpsangam.org/about/

Alternatives India
VIKALP sangam
www.vikalpsangam.org

- ACCORD (Tamil Nadu)
- Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture (national)
- Alternative Law Forum (Bengaluru)
- Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (Bengaluru)
- BHASHA (Gujarat)
- Bhoomi College (Bengaluru)
- Blue Ribbon Movement (Mumbai)
- Centre for Education and Documentation (Mumbai)
- Centre for Environment Education (Gujarat)
- Centre for Equity Studies (Delhi)
- CGNetSwara (Chhattisgarh)
- Chalakudypuzha Samrakshana Samithi / River Research Centre (Kerala)
- ComMutiny: The Youth Collective (Delhi)
- Deccan Development Society (Telangana)
- Deer Park (Himachal Pradesh)
- Development Alternatives (Delhi)
- Dharamitra (Maharashtra)
- Ekta Parishad (several states)
- Ektha (Chennai)
- EQUATIONS (Bengaluru)
- Gene Campaign (Delhi)
- Greenpeace India (Bengaluru)
- Health Swaraaj Samvaad (national)
- Ideosync (Delhi)
- Jagori Rural (Himachal Pradesh)
- Kalpavriksh (Maharashtra)
- Knowledge in Civil Society (national)
- Kriti Team (Delhi)
- Ladakh Arts and Media Organisation (Ladakh)
- Local Futures (Ladakh)
- Maati (Uttarakhand)
- Mahila Kisan Adhikar Manch (national)
- Mazdoor Kisan Shakti Sangathan (Rajasthan)
- National Alliance of Peoples' Movements (national)
- Nirangal (Tamil Nadu)
- North East Slow Food and Agrobiodiversity Society (Meghalaya)
- Peoples' Science Institute (Uttarakhand)
- Revitalising Rainfed Agriculture Network (national)
- reStore (Chennai)
- Sahjeevan (Kachchh)
- Sambhaavnaa (Himachal Pradesh)
- Samvedana (Maharashtra)
- Sangama (Bengaluru)
- Sangat (Delhi)
- School for Democracy (Rajasthan)
- School for Rural Development and Environment (Kashmir)
- Shikshantar (Rajasthan)
- Snow Leopard Conservancy India Trust (Ladakh)
- Social Entrepreneurship Association (Tamil Nadu)
- SOPPECOM (Maharashtra)
- South Asian Dialogue on Ecological Democracy (Delhi)
- Students' Environmental and Cultural Movement of Ladakh (Ladakh)
- Thanal (Kerala)
- Timbaktu Collective (Andhra Pradesh)
- Titli Trust (Uttarakhand)
- Tribal Health Initiative (Tamil Nadu)
- URMUL (Rajasthan)
- Vrikshamitra (Maharashtra)
- Watershed Support Services and Activities Network (Andhra Pradesh/Telangana)